Friday, the 11th May, 2002/27 *Vaisakha,* 1924 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock.

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Assistance for national games

*741. SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Will the Minister of YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to state:

(a) what monetary support and other facilities are given to a State for organising national and international games;

(b) the assistance given and proposed to be given to Andhra Pradesh for preparation of the 32nd National Games 2002;

(c) whether there is any proposal to ensure continued utilisation of sports equipment being procured; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SUSHREE UMA BHARTI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) There is no provision in the existing schemes for providing monetary support and other facilities to a State for organising National and International Games as such. However, in the past, Government in relaxation of the provisions of the Scheme of Assistance to National Sports Federations, had provided financial assistance to State Governments for conduct of National Games and purchase of equipments. Besides this, Central assistance is provided for creation of sports facilities under the Scheme of "Grants for Creation of Sports Infrastructure" and "Grant for Installation of Synthetic Playing Surfaces" on receipt of viable proposals from State Governments.

(b) Chief Minister of Andhra Pradesh had requested for release of one-time grant of Rs. 50.00 crores for creation of sports infrastructure for National Games to be held in Hyderbad during 2002. As no provision

exists for providing *ad-hoc* or one time grant for creation of sports infrastructure, the Chief Minister was requested on 27-11-2001 to get suitable proposals for creation of sports infrastructure formulated in accordance with the prescribed norms in the Scheme for "Grants for Creation of Sports Infrastructure".

(c) and (d) No such proposal has been received from the Government of Andhra Pradesh. However, the concerned State Government is supposed to ensure continued utilisation of sports equipments being procured by them.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, for the last two years, no National Games could be held. The Government of Andhra Pradesh, under the leadership of Shri Chandrababu Naidugaru came forward to conduct the Games, Sir, Andhra Pradesh has produced a number of champions in many fields, like badminton, wrestling and chess. Notable among them are Malleshwari in wrestling, who won the only Olympic^ Medal for India, in the last Olympic Games. Pullela Gopichand in badminton, Koneru Hampi and Harikrishna in chess. They have brought laurels to the country. The Government of Andhra Pradesh is encouraging sportsmen by giving incentives ranging from Rs. 50,000 to Rs. 25 lakhs. For conducting the Thirty-Second National Games, the Government of Andhra Pradesh is spending Rs.150 crores. So far, it has spent about Rs. 120 crores, by building seven huge stadia of high class standards. Sir, I request the Government of India to extend all financial help to the State Government for smooth conduct of the Games.

My second request to the Government of India is to give exemption on customs and other duties on the import of sports material from Germany and other countries for this particular event.

सुश्री उमा भारती : सर, सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हुं कि नेशनल गेम्स जो आन्ध्र प्रदेश को अलाट हुए है, उसकी तैयारी आन्ध्र प्रदेश में बहुत अच्छी हो रही है । भारत के राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में आन्ध्र प्रदेश की तैयारियों को देखकर मुझे लगता है कि खेलों का आयोजन अदभुत ओर चमत्कारी होगा । सर, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है कि हम आन्ध्र प्रदेश की सरकार को राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में सहयोग करें । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहती हूं कि हमारे सामने एक व्यावहारिक कठिनाई खड़ी हो हो जाती है । राष्ट्रीय खेल जो किसी राज्य को अलाट होते है । उनको अलाट करने का काम हमारा नहीं होता है, वह काम इंडियन ओलम्पिक

एसोसिसएशन का होता है । जो राज्य की ओलम्पिक एसोसिएशन होती है, उसको अलाट करते है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके । इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन की जो राज्य स्तर की इकाई होती है वह और राज्य सरकार ये दोनों आई.ओ.ए. के साथ कंसल्ट करती है । उसके बाद बैठकर निर्णय होता है कि इस राज्य में खेल होंगे । उस समय पर जो राज्य की इकाई इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन होती है और नेशनल लेवल की जो इकाई आई.ओ.ए. होती है वह मिलकर के राज्य से सारे सवाल कर लेती है कि खेलों के आयोजन में ये चीजें लगेंगी, क्या आप इनको कर पायेंगे । इसमें किसी भी स्टेज पर केन्द्र सरकार से कोई कसंल्टेशन नहीं होता है । यह सीधे-सीधे इंडियन ओलम्पिक संघ और राज्य सरकार के बीच में होता है । हमसे न तो गेम्स को अलाट करते समय कंसल्टेशन होती है, न किसी तैयारी के बारे में कंसल्टेशन होती हैं न राज्य सरकार हमसे पूछती है कि हम गेम्स के अलाटमेंट के लिए इनविटेशन भेजने वाले है । हमसे किसी भी स्टेज पर कसंल्टेशन नहीं होता है । उसके बाद में जब गेम्स अलाट हो जाते है तब राज्य सरकारें हमसे पूछने लग जाती है कि हम गेम्स कर रहे है, इसलिए आप हमारा सहयोग कीजिए । राज्य सरकारों को नेशनल गेम्स के लिए सहयोग करने के लिए हमारे यहां प्रॉवीजन नहीं हैं । फिर हम प्रॉवीजन ढूंढते है, इनको हम तीन जगह पर ढूंढते है, क्योंकि वह हमसे तीन जगह सहयोग मांगते है, एक तो इन्फ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, कंडक्ट ऑफ गेम के लिए और उपकरणों की खरीद के लिए । फिर उपकरणों की खरीद में फाइर्नेशियल एसिसटेंस टू नेशनल फेडरेशन्स होता है । उसमें से हम रास्ता निकाल कर उनको देते है । इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे यहां फिफ्टी-फिफ्टी की स्कीम होती है जिसमे फिफ्टी परसेंट के राज्य शेयर होता है और फिफ्टी परसेंसअ केन्द्र का शेयर होता है और स्पेशल कैटागरि स्टेट के लिए 25-75 का जो प्रोवीजन होता है, उसके आधार पर हम उनका सहयोग करते है । कंडक्ट ऑफ गैम्स के लिए हम विशेष रूप से वित्त मंत्रालय से कुछ रिलैक्सेशन लेकर उनको सहयोग करते है । इन सारी प्रक्रियाओं में बहुत समय लगता है । ऐसी कोई स्थिति आज तक नहीं हुई कि राज्य सरकार ने गेम अलॉट करवाने से पहले केन्द्र सरकार के साथ कसंल्ट किया हो । इसलिए अब यह स्थितियां है । जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, हमें आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पत्र प्राप्त हुआ, वह पत्र मेरे पास यहां पर भी मौजूद है । उस पत्र का उत्तर मैंने उनको तत्काल दिया बल्कि अपने उत्तर को याद दिलाते हुए एक दूसरा उत्तर भी उनको दिया । उस पत्र में उन्होंने हमें कहा कि आप हमें लम्पसम पचास करोड़ रूपए दे दीजिए । महोदय, केन्द्र सरकार के खेल विभाग के पास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिसमें हम राज्य सरकार को लम्प-सम पचास करोड़ रूपये दे दें । जैसा मैंने आपकों कहा कि दूसरे रास्ते है । वह रास्तें मैंने उनको लिखकर भेजे कि आप इन रास्तों के द्वारा जो प्रक्रिया है, उस तरीके से आप हमें अप्रोच करिए । मैं अभी तक राज्य सरकार की अप्रोच की वेट कर रही हूं । वैसे में आपके माध्यम से माननीय सांसद को यह भी जानकारी दे दूं कि उनके खेल मंत्री का पत्र भी हमें प्राप्त हुआ है, उसका भी मैंने उत्तर दिया । लेकिन अंत में मैने अपने सचिव को, खेल सचिव को अनुरोध किया है और वह कल वहां जा रहे है , यह पहले से ही तय था और इस संबंध में राज्य सरकार से बैठक करके परामर्श करेंगे । कस्टम डयूटी ऐक्जम्पशन के लिए मिनिस्टरी ऑफ फाइनेंस के साथ हमें

परामर्श करना पड़ता है । राज्य सरकार ने एक पत्र सीधा मिनिस्टरी ऑफ फाइनेंस को लिखा है, उसकी एक कॉपी हमें भी भेजी है , उसके आधार पर हम भी अपनी तरफ से मिनिस्टरी आर्फ फाइनेंस को अप्रोच कर देते है कि आप इनको रिलैक्सेशन दे दीजिए । इस तरह से यह हमारा रोल रहता है । हम उसमें शुरू से इनवॉल्व नहीं होते अलॉटमेंट में इनवॉल्व नहीं होते । जब राज्य सरकार को गेम्प अलॉट हो जाते है, तब वह हमें अप्रोच करते है । इसलिए मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि जो बातें उन्होंने हमारे सामने रखी है, उसमें आंध्र प्रदेश की सरकार खेलों को भव्य तरीके से आयोजित कर सके, इसमें हम अपने नियमों की मर्यादाओं में बंधे हुए उनको पूरी तरह से सहयोग करेंगे । केन्द्र सरकार और केन्द्र सरकार का खेल विभाग आध्रं प्रदेश के भव्य आयोजन में किसी तरह की भी कोई कमी नहीं रखेगा । मैं सदन के पटल पर ही अपना यह कमिटमेंट अपने खेल विभाग से उनको दे रही हूं लेकिन हम अपनी मर्यादाओं का उल्लघंन भी नहीं कर पाएंगे । हमारे यहां पर लम्प-सम पैसे देने का कोई प्रस्ताव नहीं है, हमारी जो स्कीम्स है, उनके अंतर्गत वे हमसे अप्रोच करें, इस संबंध में हम उनके पत्र का उत्तर देकर उनको लिख चुके है । हमारे खेल विभाग के सचिव इस बारे में इस सुनिश्चित बात करने के लिए कल स्वंय हैदराबाद जा रहे है ।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, the hon. Minister has stated about the sharing of money on 50:50 basis. Our Sports Minister, Shri Ramulu, had written a detailed letter to the Government of India for extending financial assistance for providing infrastructure. Sir, seven stadiums have already been completed. About 58 acres of land has been acquired in Gachibowli and huge complexes have come up. Tomorrow, they are launching the Asian athletics Grand Prix. Sir, about twenty-three countries are participating in the event. I demand of the Government of India to release money to the extent of 50:50 as per rules, as has been stated by the hon. Minister. We are desperately in need of money for smooth conduct of the Games.

Part (b) of my supplementary is with regard to customs and excise duties on import of sports items. Sir as a goodwill gesture, the Government of India may exempt the State from customs and excise duties, where many events are taking place. It is a fast-growing State. It is a performing State. We are in need of money.

Part (c) of my supplementary is this. Sir once the events are over, the stadiums become under-utilised. We could also see this in Delhi where many political programmes or some other programmes being held in stadiums. I demand that the Government of India should see that wherever infrastructure! facilities are availabble with international standards, national

or international events must be conducted, especially to encourage sports personnel and to put the infrastructural facilities available there to optimum utilisations.

Part (d) of my supplementary is: There is another demand of the Government of Andhra Pradesh pending with the Government of India. It is about a regional sports centre atTirupati to continue these programmes is required. And there is also another request from the Government of Andhra Pradesh for setting up of a National Rowing Academy. I request the hon. Minister to react positively on these issues.

सुश्री उमा भारती : माननीय सदस्य ने एक एक करके चार सवाल पूछ लिए हैं। उनमें से पहला सवाल है, वह इस सवाल की परिधि में है, तीन नहीं है, लेकिन जुड़े हुए हैं इसलिए मैं उनका भी जवाब दे दूंगी। पहला उन्होंने कहा है कि उनके जो खेल मंत्री हैं, उन्होंने हमसे अनुरोध किया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, मैंने आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री के पत्र के उत्तर में पहले ही यह बात लिख दी। इसमें मैंने उनको स्पैशली रिक्वैस्ट भी कर दी कि हमारी स्कीम्स के जो प्रोविजन्स है, उनके अंतर्गत आप लिखिए। उस प्रस्ताव का मैं इस घड़ी तक वेट कर रही हूं कि जैसे प्रपोज्ड नार्म्स होते हैं उसी के अंतर्गत हम उनको मनी रिलीज कर पाएंगे क्योंकि हम कितना दे सकते हैं यह कैंपिग भी हमारे यहां पर है, जैसे स्टेडियम के लिए हम कितना दे सकते हैं खेल काम्पलेक्स के लिए हम कितना दे सकते है, उस कैपिंग के अधीन जो प्रपोज्ड नॉर्म्स हैं जब उन प्रपोज्ड नॉर्म्स के अंतर्गत हमसे एप्रोच होगी तो उस समय हम उसी हिसाब से देंगे। इसलिए माननीय सदस्य की जो चिंता है, उसको मैं समझ रही हूं क्योंकि गेम्स बिल्कुल नज़दीक आ रहे है। इसलिए मैंने सारी चीज़ों का शार्ट कट निकालने के लिए अपने खेल विभाग के सचिव से कहा है कि आप कल जाइए, वहां पर बैठक कीजिए और जो प्रपोज्ड नॉर्म्स है, उनके अंतर्गत, हमारी स्कीम्स की मर्यादाओं में ही हमसे एप्रोच होनी चाहिए। उन सारी बातों का निपटारा बैठक में ही करके ले आइए ताकि हमारी तरफ से अच्छे तरीके से आंध्र प्रदेश की सरकार खेलों का आयोजन कर सकें।

सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वासन देती हूं कि हमारे यहां से इस बात में कोई कसर नहीं छूटेगी। हम वित्त मंत्रालय में भी जाएंगे, यद्यपि उन्होनें सीधे वित्त मंत्रालय को लिखा है लेकिन उसकी एक कॉपी हमें भेजी है, इसलिए उस कॉपी को आधार बनाकर वित्त मंत्रालय के पास ही स्वयं जाएंगे कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो भी सहयोग मांगा है, वे उस सहयोग को पूरी तरह से करे। मैं उन्हें आश्वस्त करती हूं कि यद्यपि इसमें हमारा कोई रोल शुरू से आखिर तक नहीं रहता है लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और मैं उन्हें आश्वस्त करती हूं कि वे निश्चित रहे। जिस प्रकार की तैयारियों की खबरें आंध्र प्रदेश से मिल रही हैं मुझे लगता है कि नेशनल गेम्स का आयोजन करने में आंध्र प्रदेश बाजी मार ले जाएगा और बहुत excellent लेवल के खेल वहां पर होगें

दूसरी बात जो उन्होंने मेरे सामने रखी है, वह रीजनल सेंटर्स के बारे में है। रीजनल सेंटर्स के लिए भी स्पोट्‌र्स अथॉरिटी आर्फ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल है, वे वहां पर गए थे और वहां जाकर उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए जो सब-सेंटर की बात वहां पर आई है, वह कैसे हो, इसके बारे में वे बैठक करने गए है और मै अभी वेट कर रही हूं कि वह रिपोर्ट मुझे मिले।

सभापति महोदय, तीसरी बात उन्होंने यह कही है कि जब एक बार कोई इनफ्रास्ट्रचर खड़ा हो जाता है तो दिक्कत आती हैं कि इनफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कैसे हो ? क्योंकि एक बार गेम्स आयोजित हो जाते हैं तो उसके बाद उस इनफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना बहुत कटिन काम हो जाता हैं। उसकी भुक्तभोगी मैं स्वय हूं। यहां दिल्ली में बड़े-बड़े स्टेडियम सफेद हाथी की तरह बने हुए खड़े है। हम फेडरेशन्स को कई बार अनुरोध करते हैं कि आप अपनी प्रतिस्पर्धाएं हमारे यहां पर आयोजित कीजिए। प्रतिस्पर्धाओं को आयोजित करने का इनीशिएशन लेना हमारे काम नहीं होता है। हम एनकरेज कर सकते हैं हम सपोर्ट कर सकते है। हम अलग-अलग स्कीमो के प्रोविजन्स के अंतर्गत उनको सहयोग दे सकते है लेकिन यह सारा काम फेडरेशन्स का होता है। आंध्र प्रदेश के जो खेल संघ है या जो अखिल भारतीय स्तर के खेल संघ हैं मैं चाहूंगी कि वे वहां पर इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं को आयोजित करें। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि आंध्र प्रदेश की खेल प्रतिभाओं ने पूरी दुनिया में भारत का और आंध्र प्रदेश का नाम ऊंचा किया है और आंध्र प्रदेश की सरकार में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने में इतना बढ़कर काम किया है कि आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए है। अब जितना हमसे बनता है इस मामले में हम सहयोग करते है। मैं तो बार-बार इस सदन में अनुरोध करती रही हूं कि खेल विभाग का जो बजट है, वह बिल्कुल गऊ के ग्रास के बराबर होता है, जैसे भोजन करते समय लोग थोड़ा सा चींटी के लिए और गऊ के लिए निकाल कर रख देते है। ऐसा ही खेल विभाग का बजट लगता है। चाहे आप केन्द्र सरकार का खेल विभाग देख लें चाहे राज्य सरकार का खेल विभाग देख लें, लगभग स्थिति यही रहती है। मैं तो माननीय सदन से अनुरोध करती हूं जो हमारे देश का सर्वोच्च सदन है , कि आप ऐसी स्थितियों का निर्माण कीजिए जिससे खेल विभाग का बजट बढ़े और माननीय सदस्य, खासकर राज्य सभा के जो माननीय सदस्य है, उनके जो सांसद विकास निधि होती है, उसका उपयोग वे इस प्रकार की चीजों के लिए करें, तो निश्चित रूप से इसका लाभ होगा।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: मान्यवर, उमा भारती जी ने आंध्र प्रदेश के लिए जो ऐश्योंरेंस दिया है,उसके लिए हम सब उनके आभारी है लेकिन ...(व्यवधान)...

डा. अलादी पी. राजकुमार : ऐश्योंरेंस नहीं दिया है, तारीफ की है उन्होंने। स्टेट गवर्नमेंट ने इनफ्रास्ट्रक्चर बनाया है...मैं आपको समझा रहा हूं।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता : मैं समझ रहा हूं, आपसे ज्यादा समझता हूं, आप चिंता न करें। महोदय माननीय मंत्री महोदया पूरे देश की खेल मंत्री है, उनको पूरे देश के खेल मंत्रालय और स्कीमों के बारे में सोचना चाहिए। अभी मंत्री महोदया ने कहा कि खेल विभाग को बहुत कम बजट ऐलोकेशन होता है। महोदय, हर खेल को, जैसे क्रिकेट छोड़ दिया गया क्रिकेट कट्रोंल बोर्ड के जिम्मे, दूसरे खेल छोड़ दिए गए कोई ओलम्पिक एसोसिएशन है, कोई स्टेट ओलम्पिक एसोसिएशन है, इनमें कितनी इनकम होती है ? आप क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में ही लीजिए कितनी इनकम इनकी होती हैं लाखों करोड़ों रूपए इसमें हर मैच में बचते है. उसका क्या युटिलाइज़ेशन होता है, क्या नहीं होता है, इसके लिए आपको एक नेशनल स्पोट्र्स पॉलिसी बनानी चाहिए। जिसके तहत पूरे देश में आप एक बैलेंसिंग सिस्टम रखें कि किस क्षेत्र में कौन सा खेल ज्यादा उठाया जा सकता है। कहां पर क्या माइन्ड सेट है, कहां पर क्या है, जैसे फुटबाल वेस्ट बंगाल में एक बहुत पोप्युलर गेम है, नॉर्थ और साउथ में क्रिकेट है तथा और दूसरे खेल है। स्पोट्र्स मंत्रालय को एक बैंलेसं रखकर पूरे देश के लिए एक नेशनल स्पोट्र्स पॉलिसी बनानी चहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास ऐसी कोई स्कीम है या फिर ऐसा करने का कोई विचार है या आप खाली क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जिम्मे क्रिकेट छोड़ देंगे या दूसरी एसोसिएशन्स के जिम्मे दूसरे खेल छोड़ देंगे और वहां पर सब मैंनिपुलेशन होता रहेगा।

सुश्री उमा भारती : सभापति जी, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है लेकिन यह इस सवाल की परिधि में कहीं नहीं आता है। मै आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगी कि उनकी चिन्ता से हम सब अवगत है लेकिन चूंकि खेल कनकरेंट लिस्ट में नहीं है और दूसरी बात यह है स्पोट्र्स फेडरेशन की जो आटोनोमिटी है, हम उसमें दखलंदाजी नहीं चाहते है। आज सब तरफ यह बात चल रही है कि स्वायतत्ता होनी चाहिए, निजीकरण होना चाहिए तो खेलों का सरकारीकरण क्यों हो ? सरकार की खेलों में दखलंदाजी क्यों हो ? खेल संगठित तरीके से काम करें, इस धर्म का हम निर्वहन करते है और अगर वे अनैतिक आचरण करते है तो उसके नियंत्रण के जितने भी उपाय होते है, वे हम आजमाते है। सभापति जी, माननीय सदस्य ने आंध्र प्रदेश के बारे में जो टिप्पणी की है, मुझे अभी-अभी जानकारी दी गई है कि एक करोड़ रूपये हम ट्रैक के लिए आलरेडी एप्रूव कर चुके है तथा कस्टम डयूटी के रिलेक्सेशन के लिए भी डिसिजन हो चुका है। हमारी तरफ से जो होना है वह भी हो चुका है। मेरा एक निवेदन है कि इस प्रकार की टिप्पणी करने से पहले एक लैटर, जो मैंने उन्हें लिखा है उसे पढ़कर सुना दूं, इसमें मैंने आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से बार-बार अनुरोध किया है कि आप हमें हमारी स्कीम से, जैसा हम आपको दे सकते हैं उस प्रकार से प्रपोजल बनाकर भेज दीजिए ताकि वह हम आपको दें। हम फिर भी देगें। मैं अपनी तरफ से एप्रोच करके खेल ससिव को अपने इनिशिएशन पर भेज रही हूं कि आप वहां जाइए और जैसे प्रस्तावों में हम दे सकते है वैसे प्रस्ताव बनवाने की तैयारी वहां से करके आइए। हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है और न ही हम खाली-पीली कोई एश्योरेंस दे सकते है। यह सर्वोच्च सदन है इसलिए यहां झूठे और एम्पटी प्रोमिसिस नहीं दिए जा सकते हैं

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: अगर राष्ट्रीयकरण या सरकारीकरण नहीं करना है तो उन्हें फंड्स किस लिए चाहिए ? सभापति जी,ये इसीलिए बड़ा एलोकेशन चाहते है।

DR.T. SUBBARAMI REDDY: Sir, my question pertains to monetary support being given to the Ministry of Sports. What I understand from the hon. Ministers reply is, for the Ministry of Sports, a very small amount has been allocated in the Budget. The hon. Minister has also said that they do not want to interfere between the State Governments and the Olympic Association. I am very much surprised to hear this from the Minister, because that may be just a normal convention which is followed. I want to know what is the Sports Ministry doing in this regard? Sir, I would like to say that all the hon. Members of this House are with her in demanding more funds for her Sports Ministry. In all the countries of the world, a lot of encouragement is given to sports. India has many talented sports persons, but we always fail at the international level, because we have no money, no encouragement no inclination, no inspiration, no determination and no devotion to develop our creativeness.

MR. CHAIRMAN: I think you have to be brief. It is just the first question, and only two Members have put their questions.

DR.T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I will be brief. I would like to know from the hon. Minister whether any efforts are being made to increase the allocation for sports. You are part of the NDA Government, so, you have every right to demand for more funds, on behalf of all of us.

The second part of my supplementary is this. Simply saying that the Olympic Association is doing everything, is not sufficient. Is it not the duty of the Ministry of Sports to interfere, guide and coordinate in these activities? My colleague rightly mentioned that a number of beautiful stadiums are there, but no sport activity is taking place there. Is it not your duty to ensure that such nice stadiums are used properly and National Games are held there? I would like to have a concrete reply from the Ministry in this regard.

सुश्री उमा भारती : सभापति जी, पहली जो बात इन्होंने कही है, उसके संबंध में मैं बताना चाहती हूं कि इन चार सालों में, सर, जब हम सदन में खड़े होते है तो पिछली सरकार और अगली सरकार की तुलना नहीं कर सकते है, हम कंटीन्यूटी की ही बात करेंगे। मैं इतना कह सकती हूं कि इन चार सालों में स्पोर्ट्स का बजट लगभग दुगना हुआ है। सभापति जी, आत्मस्तुति और परनिन्दा

राजनीति के अंग हो गए है कि हम अपनी प्रशंसा करें और दूसरे की निन्दा करें । मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि जब-जब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनी हूं 1998 में बनी, 1999 में इंडिपेंडेंट चार्ज मिला और अब कैबिनेट के तौर पर स्पोर्ट्स मिला है । इस साल स्पोर्ट्स का 35 करोड़ रूपये का बजट बढ़ा है, इससे पहले भी चालीस-पचास करोड़ तक बढ़ता चला गया है और आज की स्थिति में आते-आते लगभग दुगना हो गया । मैं यह भी बताऊं कि इस बजट में मितव्ययता और फिजूलखर्ची को रोकते हुए हम ही है जो राज्य सरकार में जो विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में सहयोग करते है । यहां तक कि इवेंट्स को भी क्रीएट करने में या इवेंट्स जितने भी वे बनाते है, उनका हम स्वागत करते है । एथलेटिक्स ट्रैक्स, हाकी के टर्फ या और भी अन्य प्रकार के जितने भी खेलों के इन्फ्रास्ट्रक्चर होते है, उसमें जो स्पेशल केटेगरी वाले स्टेट्स है जैसे नार्थ ईस्ट या जो अन्य स्टेट्स है, उनमें 75-25 के अंतर्गत और बाकी राज्यों में 50-50 शेयरिंग के अंतर्गत पूरी मर्यादाओं का पालन करते हुए हम कोशिश करते है । मैं यह भी बता दूं कि कोई राज्य सरकार ऐसी नहीं है जो हमारे सहयोग के बिना कोई काम कर रही हो । हम कम में भी उनका सहयोग करते है और वे बेचारे भी अपने कम बजट में बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करते है ।

दूसरी बात उन्होंने कही है कि वे हमारा इसमें किस प्रकार से सहयोग कर सकते है । इसमें दो तीन बातें है जिसमें कि वे हमार सहयोग कर सकते है । एक तो एमपीएलएडी फंड से जो सब माननीय सदस्य इस माननीय सदन के यहां पर मौजूद है । इस सदन के सदस्यों को तो वैसे भी एक बहुत अच्छा अधिकार मिला हुआ है, चूंकि वे पालियामेंट्री कांस्टीटुएंसी की बांउड्री से बंधे हुए नहीं है, इसलिए वे एक विशेष जगह पर भी अलग-अलग नामों पर प्रयोग कर अपनी जो सांसद विकास निधि मिली हुई हैं उसका उपयोग कर सकते है । केन्द्र सरकार को तो जब-जब हम अनुरोध करते है वे बजट बढ़ा देते है । हम उनको जब बताते है और बजट के पहले हम अपनी पूरी स्थिति वित्त मंत्रालय के सामने रखते है तो वह हमें मिल जाता है । बाकी हमने विभिन्न मंत्रालयों को लिखा है कि वे अपने तरीके से हमारा सहयोग करे । हमने स्पोर्ट्स फेडरेशन को भी कहा है । जो बात पहले माननीय सदस्य ने कही, उसको मैं फिर दोहरा रही हूं कि वे विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं को आयोजित करें । जो हम इन्फास्ट्रक्चर तैयार करते है वह बना रहे । कोई ऐसी स्थिति न आ पाए कि वह बिगड़ जाए । इसमें हम खुद भी उनको कहते है, उनको अनुरोध भी करते है कि आप अपनी तरफ से यहां पर आइए और आयोजन करिए और उसमें हम अपनी स्कीम्स के अंतर्गत जितना बनेगा आपका सहयोग करेंगे । हमने शिक्षा मंत्रालय को एक पत्र लिखा हुआ है जिसमे हमने उनसे अनुरोध किया है कि आप अपने बजट का एक छोटा सा हिस्सा खेल की अधोसंरचना, इन्फ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए लगाएं । जब एजूकेशन का इन्फ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा कर रहे है उसी समय उसको थोड़ा सा खड़ा कर दें । शिक्षा मंत्रालय का बजट बड़ा होता है कि अगर वे अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करते समय पांच परसेंट लगाकर स्पोर्ट्स के इन्फ्रास्ट्रक्चर को इसके साथ ही खड़ा कर दें तो

यह अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा । मैं सदन का इसी मामले में सहयोग चाहती हूं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : माननीय मंत्री महोदया ने अपने इस प्रश्न के पहले पार्ट में जवाब दिया है कि राज्यों में स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़े करने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से सहयोग दिया जाता है और स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रीएट करने के सिलसिले में "साई"के सेंटर्स खोले जाते है । मैंने पिछले से पिछले हफ्ते एक प्रश्न पूछा था । रिटर्न में उसका जवाब आया है कि पिछले तीने वर्षो में इस दिशा में साई के इतने सेंटर्स खोल गए है । मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहा कि पिछले तीन वर्षो में हमारे देश में तीन खेल मंत्री बने और न खुले तीनों खेल मंत्रियों ने अपनी अपनी कांस्टीटुएंसी में साई के सेंटर्स खोल दिए । ढिंडसा साहब ने बादल में खोला, शाहनवाज जी ने किशनगंज में खोल लिया और उमा जी ने टीकमगढ़ में खोला है । मैं सिर्फ एक पालिसी मैटर की बात जानना चाहता हूं कि साई सेंटर्स सचमुच कहां खोले जाने चाहिए, यह केन्द्र सरकार तय करती है या राज्य सरकार से आप राय लेते है ? क्या राज्य सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार की फीड बैंक के बाद आप डिसिजन लेते है या आप खेल मंत्री हो गए और अपने गांव में साई सेंटर्स खोलना है, या पालिसी है ?

सुश्री उमा भारती : सर, साई सेंटर, अगर हम मंत्री न होते तब भी लिखते कि हमारे यहां पर होना चाहिए । मैं उनको बताऊं कि जो साई, स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया है, उसके अलग –अलग प्रकार के सेंटर्स होते हैं । बैंगलोर में हमारा सेंटर पहले से है, पटियाला में हमारा सेंटर पहले से है ।मुझसे पहले की सरकार के समय से भोपाल और लखनऊ के लिए प्रस्ताव था । मेरे आने के बाद तो वह प्रस्ताव जो आखिरी स्टेज पर था उसको अंजाम दिया गया । लेकिन सर, हमने कोई अपराध तो नहीं किया है । हम खेल मंत्री होने के साथ अगर सांसद हैं और अपनी कांस्टीटुएसीं की अगर फिक्र कर लेते है तो कोई अपराध तो नहीं है । लेकिन मैं माननीय सदस्य को , मैं सदन को यहा प्रामिस करती हूं कि मैं वह ब्योरेवार सूची भेज दूंगी । मैं माननीय सदस्य को और पूरे सदन को जानकारी के लिए वह ब्योरेवार सूची भेजने के लिए तैयार हूं कि जहां पर हमने ...(व्यवधान)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, I have an objection.. .*(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: It will be unnecessarily delayed ... *(Interruptbns)*

श्री सजंय निरूपम : गाइडलाइन क्या है ? जहां टेलेंट होगा वहां साई सेंटर खोला जाएगा या जहां के मंत्री होंगे साई सेंटर खोंलेंगे ?

सुश्री उमा भारती : मैं अब दूसरी बात पर आ रही हूं ...(व्यवधान)

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: What is the guideline?...*{Interruptions)...* The hon. Member is asking, "What is the guideline?". ..*{Interruptions)...* This is not the way.. .*{Interruptions).* ..What is the guideline?...*{Interruptions)...*

प्रो. अलका क्षत्रिय : आप कहती है, आप पहले सांसद है । यहां सब सांसद बैठे है, सब मांग करेंगे तो आप सबको देंगी...(व्यवधान)

सुश्री उमा भारती : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए वह पूरी सूची भेजने के लिए तैयार हूं जहां पर कि हमने इन चार-पांच सालों में स्पोट्र्स अथारिटी आफ इंडिया के सेंटर्स खोले हैं कहीं डे बोर्डिंग खोला है, कहीं कुछ खोला है । वह पूरी सूची मैं देने के लिए तैयार हूं और लगभग हमने सभी राज्यों को कवर किया है । किसी माननीय सदस्य की पार्लियामेंटरी कंस्टीटुएंसी छूट गई हो तो वह अलग बात है । सहयोग हम राज्य सरकार से साई ट्रेनिंग सेन्टर खोलने में या सब सेन्टर खोलने में इतना लेते है । कि हम उनसे जमीन लेते है । सर,अभी मेरे पास वह सूची मौजूद नहीं हैं । इसमें हम सब से पहले तो पिछड़े हुए राज्यों को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं । इसमें हम ऐसा कहीं कोई किसी प्रकार के भेदभाव का बर्ताव नहीं करते है । इसलिए सर, मैं माननीय सदन से अनुरोध करना चाहती हूं कि आप ...(व्यवधान)

डा. अबरार अहमद : क्या इस संबंध में आपके कोई मापदंड, कोई नीति या कोई दिशा-निर्देश है ?...(व्यवधान)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : यह कोई तरीका है ।

श्री संजय निरूपम : प्लीज, सिंहल साहब ।

सुश्री उमा भारती : सर, उसके मापदंड है । ...(व्यवधान)....

श्री सजय निरूपम : एक मिनट ...(व्यवधान)...उमा जी, बुनियादी प्रश्न यह है कि साई सैन्टर कहां खोलना है यह कैसे तय होगा, उसकी कौन सी गाइडलाइन्ज़ है ?...(व्यवधान)...

श्री विक्रम वर्मा : वह सैन्टर में है और पूरे देश का मध्य केन्द्र है, सेन्टर में डिमांड थी, इसलिए भोपाल को किया गया था, क्योंकि वर्षो से डिमांड थी ।

श्री संजय निरूपम : कोई भोपाल के खिलाफ नहीं है, कोई ...(व्यवधान)...

श्री विक्रम वर्मा : जो आदिवासी बहुल प्रदेश है, सर्वाधिक आदिवासी जिस प्रदेश में रहते हो और टेलेंट हो...(व्यवधान)...

सुश्री उमा भारती : सर, भोपाल का सैन्टर तब खुला जब मैं वहां से सांसद् नहीं थी।...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : न हम भोपाल के खिलाफ है और न हम लखनऊ के खिलाफ है , मैं यह जानना चाहता हूं कि गाइडलाइन्ज़ क्या है ? यह कौन तय करेगा कि साई सैन्टर कहां खोला जाना चाहिए ?

सुश्री उमा भारती : सर, साई सैन्टर खोलने के तीन रास्ते है । एक तो कई बार माननीय सदस्य स्वंय लिखते हैं कि हमारे क्षेत्र में स्पोर्ट्स अथारिटी आफॅ इंडिया की कोई स्कीम लागू की जाए, दूसरा कई बार हमको राज्य सरकार लिखती है , और तीसरा कई बार हम स्वंय पोटेंशियल ढूंढ़ते हैं कि साई ट्रेंनिंग सैन्टर कहां पर होना चाहिए और किस प्रकार की गेम के लिए होना चाहिए, उसके हिसाब से हम करते है । जब ये तीनों चीजें हमारे सामने आती है तो हम बैठ करके विचार करते है कि उसकी उपयोगिता हो पाएगी या नहीं और उसके हिसाब से हम निर्णय लेते है । इसमें कहीं कोई पोलिटीकल मोटीवेशन या किसी एक व्यक्ति के लिए प्रेफ्रेंस यह कहीं माइंड में नहीं होती है । सर मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह अनुरोध कर रही हूं और मैं यह वचन दे रही हूं कि हम आपको पूरी सूची भेजेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि हो सकता है कई माननीय सदस्य जहां के है वही पर साई सैन्टर हो और उनको पता नहीं हो । यह भी मैं उनकी जानकारी में ला दूंगी और आ जाएगा, अभी चूकिं मेरे पास लिस्ट मौजूद नहीं है क्योकि यह प्रश्न की परिधि में कहीं था ही नहीं , नहीं तो में पूरी लिस्ट इस सदन में पेश कर देती, लेकिन मैं यह लिस्ट पेश कर दूंगी।

SHRIDIPANKAR MUKHERJEE: It should be placed on the Table of the House. What are the guidelines for allocating money and for opening a SAI Centre? That is the question. We are not asking for a list. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: That question was not originally put to her. ..*(Interruptions)*...

सुश्री उमा भारती : सर, मैंने उसका पूरा उत्तर दे दिया कि उसके तीन तरीके होते है। ...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी : आपने कहा कि एम.पी.से चिट्ठी मिलती है, तो यह कोई गाइडलाइन है। यह क्या है ? पार्लियामेंट का हम कोई..(व्यवधान)...

AN HON. MEMBER: She is not getting the question.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: What are the guidelines? Is it that a letter from a Member of Parliament is a guideline for opening a SAI

Centre? Is this the kind of reply for which we have come to Parliament? *...(Interruptions)...*

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : अभी तक यही चलता आ रहा है ।

श्री दीपांकर मुखर्जी : इसलिए तो नया चलना चाहिए । ...(व्यवधान)....

सुश्री उमा भारती : सर, हम तो राज्य सरकारों से, मैंने आपको पहले कहा कि तीन तरीके होते है । राज्य सरकारें कई बार हमें खुद लिख देती है, कई बार माननीय सदस्य लिखते है, कई बार सिर्फ हम पोटेंशियल के कारण निर्णय लेते है और उन तीनों निर्णयों में हम राज्य सरकार से कसंल्ट करते ही है । इसलिए सर, हम कहीं किसी प्रकार के भेदभाव का बर्ताव नहीं करते है । मैं माननीय सदस्य से कहूंगी ...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी : यह तो चोर दाढ़ी में तिनका वाली बात हो रही है । भेदभाव की बात तो हमने की ही नहीं है We only want guidelines. You say, "These are the guidelines as per which this is done सिपंल एक सेंटेंस कहें, आप बोले जा रहे है, बोले जा रहे है ।...(व्यवधान)....

सुश्री उमा भारती : मैं तीन बार बता चुकी हूं कि इस तरीके से होता है ।...(व्यवधान)...मैं तीन बार इसको बता चुकी हूं । ...(व्यवधान)

श्री सभापति : हो गया , नहीं-नहीं,, I have not asked you. I have permitted Shri Natwar Singh *...(Interruptions)...*

सुश्री उमा भारती : मैंने तीन बार गाइडलाइन्ज रिपीट की है ।

श्री के. नटवर सिंह : नहीं, हम आपके आभारी हैं, क्यों आप ...(व्यवधान)

सुश्री उमा भारती : मैं लड़ने के मूड में नहीं हूं ...(व्यवधान)

श्री के. नटवर सिंह : किसी से लड़ने के मूड में हो ही मत, क्यों किसी से लड़ती हो । मैं तो यह कह रहा हूं कि मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिए है उसमें ऐसा लगता है कि आपने कहा बहुत कुछ है और बताया कुछ नहीं । इसको अग्रेंजी में कहते है -— you have said a lot, but conveyed nothing. वह भी एक हुनर है | It requires a great deal of skill to speak so much and say nothing concrete.The difficulty is *...(Interruptions)...*

सुश्री उमा भारती : आप मंत्री रहे हो , आप ही से तो सीखा है ।

श्री कें नटवर सिंह : तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं । शायद थोड़ा –बहुत मेरा अनुभव वहां पहुच जाए तो मुझे खुशी होगी । तो मैं यह कह रहा हूं कि क्या आपके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने कोशिश

की है कि निकट के देश, जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना एकाध जिम्मेदार लोग जिनको कि खेलों का कुछ ज्ञान हो और वे सिर्फ दौरा करने न जाएं, ऐसे लोगों को जरा वहां भेजिए। जैसे चीन में 2008 में ओलांपिक्स हो रहे है और अभी से तैयारी शुरू हो गई है। अगर ओलंपिक्स गोल्ड मैडल्ज़ में चाइना नंबर तीन पर आ सकता है और हम एक ब्रांज मैडल मिलने पर इतना कूदते है कि मानो दुनिया फतह कर ली हो। मैं तो आप के सामने अपनी बात रखना चाहता हूं कि अगर आपके इरादे भेजने के है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उस पर विचार कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप अमेरिका भेजिए यूरोप भेजिए, आप पड़ौसी देशों में भेजिए। थाईलैड को गोल्ड मैडल मिलते है, मलेशिया को गोल्ड मैडल मिलते है, सिंगापुर को मिलते है, चायना का तो कुछ कहना ही नहीं है। आप वियतनाम को पूछिए कि उस की स्पोर्ट्स बॉडीज कैसे काम कर रही है। मुझे पता है कि यहां मल्टिप्लिसिटी ऑफ स्पोटर्स एसोसएशन है। मैं भी ऑल इंडिया टैनिस फेडरेशन का 4 साल के लिए प्रेसीडेंट रह चुका है मुझे पेचीदगियां मालूम है और मेरे ख्याल में अगर हम को इजाजत हो जाए तो अगले सेशन में आधे घंटे का डिस्कसन कर लीजिए जिस में सारे सवालों पर चर्चा हो सकती है और हम जो कुछ आप को बता सकते है, उस के लिए आप की खिदमत में हाजिर है।

सुश्री उमा भारती : सभापति जी, माननीय सदस्य इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य है। उन से हम ने बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया है, लेकिन मैं उन की जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना विजिट की तैयारी पिछले साल ही थी और वास्तव में हमें इनविटेशन भी आ गया था, लेकिन उसी समय फ्रो -एशियन गेम्स 26 मार्च से 4 अप्रैल तक प्रस्तावित रहे और दोबारा नई डेट आ गयी। अभी हम चाहते है कि ये सब फॉर्मलिटीज हो जाएं, उस के बाद हम जाएं। इसलिए अब फिर से विचार चल रहा है कि यह टीम लेकर चाइना विजिट के लिए जाएं। इस मामले में चीन से सीखा जाए, उस को अपना गुरू बनाया जाए कि उन्होंने किस प्रकार से कम समय में खेलों में तरक्की की है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह भी जानकारी दूं कि अभी "फिक्की" के एक कार्यक्रम मे आपस की बातचीत के बाद और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ कसल्ट करने के बाद एक विचार चल रहा है जो अभी विचार के लेवल पर है कि 2012 की ओलंपिक बिड के लिए भारत की ओलंपिक एसोसिएशन तैयारी करे। इस के लिए मै माननीय सदन के सभी सदस्यों का आशीर्वाद चाहूंगी कि यह संकल्प जो इंडियन ओलंपिक संघ का सरकार के साथ मिलकर आ रहा है, इस में हमें आप सभी का सहयोग मिले।

सभापति महोदय, यह सत्य है कि हमें छोटे-छोटे देशों से भी सीखना पड़ेगा कि वह कैसे इतनी प्रगति करते है। इस के लिए सब से पहले हमें खेलों से ऐसे लोगों की दखलंदाजी खत्म करनी पड़ेगी जिन का कि खेलों से कोई लेना-देना नहीं है। इस के लिए हम ने पहली शुरूआत अर्जुन अवार्ड की स्कीम के रूप में आमूल-चूल परिवर्तन कर के की है। महोदय, अगर कोई खिलाड़ी

जीतकर आता है तो वह चाहता है कि उस को सम्मान मिले और वास्तव में सम्मान उसी को मिले जो उस की पात्रता रखता है। इस के लिए हम ने दूसरा भी परिवर्तन किया है जिसकी मैंने अभी घोषणा की है और उस के इम्पलीमेंटेशन के संबंध में डिपार्टमेंट को बोला है कि जो भी खिलाड़ी ओलम्पिक में गोल्ड मैडल लेकर आएगा, उस को हम एक करोड़ रूपया देंगे और हम अपने कैश अवार्ड की स्कीम में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। लेकिन यह रकम तब देंगे जब वह जाकर आएगा। वह कैश अवार्ड जीत सकें, इसके लिए भी हम अपनी तरफ से अकैड्मीज की स्थापना कर के पूरी तैयारियां कर रहे है। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा था कि मैंने खाली बोला है।मैंने बोलने के बीच में भी आश्वासन दिया है, महोदय मुझे अपने बचाव में बोलना पड़ता है क्योंकि जो आरोप लगते है, उन को कोई आधार नहीं है। इसलिए मुझे अपने बचाव में बोलना पड़ा है, लेकिन मैंने कहा है कि हम अपनी मर्यादाओं के अंतर्गत पूरी तरह से कमिटेड है। महोदय, इन चार सालों में खेलों में जो क्रांति आई है और देश में जो परिवर्तन आया है, उस का माननीय सदन गवाह रहा है और पूरा देश गवाह रहा है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को उन के अमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद देती हूं।

MR. CHAIRMAN: Already, 35 minutes have passed. Only one question has been done. Now we will go to next question. Question No. 742. *(Interruptions).*

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी : सभापति महोदय, उन का बुनियादी सवाल था कि आंध्र प्रदेश में नेशनल या इंटरनेशनल गेम्स की तैयारी के लिए मॉनीटरी फंड दिया जाए। यह बेसिक क्यूश्चन था।

श्री सभापति : यह क्यूश्चन हो गया। अब अगला क्यूचन आएगा।

श्री रूमान्डला रामचन्द्ररया : मान्यवर, मैं आन्ध्र प्रदेश से संबंध रखता हूं। मुझे समय...(व्यवधान)...

श्री सभापति : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री रूमान्डला रामचन्द्रध्या : सर, जब खेल जाएंगे तब समय मिलेगा ? यह कहां तक न्यायोचित है ?

श्री सभापति : जब इस विषय पर हाफ एन अवर डिबेट होगी, तब समय मिलेगा

Next question.

Shri Brahma..........*(Interruptions)....* Shri Brahma. ...*(Interruptions)...*

We have already spent 35 minutes on this Question.

श्री रूमान्डला रामचन्द्ररया : सर, वन ऑवर होने दीजिए। सारे भारत में कोई गोल्ड का चान्स नहीं आ रहा। ...(व्यवधान)

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी : सर, इसमें कोई एक घंटे, आधे घंटे की बात हो जाए, तो ठीक रहेगा।

श्री सभापति : हां, हो जाएगी। अगले सेशन में बहस हो जाएगी।

Central University in Bodoland Area

*742. SHRIURKHAO GWRA BRAHMA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have any plan to set up a Central University in Assam, particularly in the Bodoland area;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) The tripartite peace talks involving the representatives of the Central Government, Government of Assam and Bodo Liberation Tiger are continuing to find a lasting peaceful solution of the Bodo issues, which include, *inter-alia* setting up of Centrally funded educational institutions in Bodoland area.

SHRI URKHAO GWRA BRAHMA: Sir, I have seen the reply given by the hon. Minister, but I am not satisfied with the answer. The answer is incomplete. My question was relating to the Government's plan for swetting up a Central University in the Bodoland area of Assam, but the answer given by the hon. Minister is about setting up Centrally-funded educational institutions. What is a Centrally-funded education institution? What does it mean? I fail to understand the meaning of it. The hon. Minister has mentioned about the peace negotiations going on with an extremist outfit, the Bodo Liberation Tigers. Presently, the negotiations are going on. But, duringthe peace negotiations, I remember, the Government of India had committed to set up of a Central University in Assam, particularly, in the Bodoland area.That was the commitment made by the Central Government, and the decision was also endorsed by the State Government of Assam. It has now become a public commitment. Then, why is the Government trying to retreat from its original commitment?

MR. CHAIRMAN: Please put the question.

SHRI URKHAO GWRA BRAHMA: This is my first question. The